

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, सोमवार, ११११ १९४१-नवम्बर ११, २०१९ Kartika 20 Monday, Saka 1941–November 11, 2019	

भाग-१(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ाएँ

गृह (गुप-९)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर ०७, २०१९

संख्या प. ३०(२)गृह-९/२०१८ :- यतः राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात रक्षा विभाग के Storage of ammunitioan (आयुध भंडारण) प्रयोजनार्थ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में निम्न भूमि का अर्जन किये जाने का आशय रखती है:-

क्र. सं.	ग्राम/चक का नाम	मु.न./प.न.	निजी भूमि (हैक्टेयर में)		कुल भूमि (हैक्टेयर में)
			नहरी	बारानी	
१	८ LLG	५२,५३,७० से ७३,९० से ९३, १०६ से १०९, ११३	१२.९०६	७५.२३८	८८.१४४
२	९ LLG	६ से ११, १६ से २१	४३.७५६	०.८८६	४४.६४२
३	१० LLG	१८ से ६०	२०३.७२	४६.५६४	२५०.२८४
४	११ LLG	६ से ९, २० से २३, ३४ से ३७, ४६ से ४९	९८.७४५	०.०००	९८.७४५
५	१२ LLG	२	२.७५९	०.०००	२.७५९
		कुल निजी भूमि:-	३६१.८८६	१२२.६८८	४८४.५७४ (है.)

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु एजेन्सी डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव, Centre for Development Communication & Studies, १३३ देवीनगर, नन्नु मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर को नियुक्त करती है।

उपरोक्त एजेन्सी डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव, Centre for Development Communication & Studies, १३३ देवीनगर, नन्नु मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि से प्रभावित गांवों/चकों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१६ के प्रावधानानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

१. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों/चकों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों/चकों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों/चकों में संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ किया जावेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु एजेन्सी

डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव,

Centre for Development Communication & Studies,

133 देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

पी.सी.बेरवाल,

विशिष्ट शासन सचिव,

गृह विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।